I. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :—

(i) 1975–76 के वर्ष के लिये रिचर्डसन एन्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, बंबई का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, लेखों पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ii) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[Placed in Library. See No. LT-29/77 for (i) and (ii)]

II. उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 162 (ई), दिनांक 14 फरवरी, 1977 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[Placed in Library. See No. LT-47/77 for (i) and (ii)].

REFERENCE TO REMARKS BY SHRI MORARJI R. DESAI WITH REGARD TO WOMEN

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI R. DESAI): With your permission, Sir, I should like to refer to the controversy which has arisen about some remarks that I made during elections in reference to women as it was considered. I do not want in any way to accentuate the controversy or further it. I should like it to be ended I regret very much that such a contingency should have arisen, and I shall try to see that such a thing never arises in future.

SHRI TRILOKI SINGH (Uttar Pradesh): With your permission, Sir, may I make a submission? .... (*Interruptions*).

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported decision of the U.S. Government to sell arms to Pakistan

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Calling attention motion. Shri Prakash Veer Shastri.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार बेचे जाने के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका के कथित निर्णय की ओर मैं विदेश मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराता हूं।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): श्रीमन्, संयुक्त राज्य अमरीका के वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से 29 मार्च, 1977 के समाचार-पत्रों में प्रकाशित यह खबर सरकार की निगाह में आई है कि अमरीकी राष्ट्रपति ने 20 अरब डालर से अधिक मूल्य के हथियारों की बिक्री की मंजूरी पाकिस्तान सहित कुछ देशों के लिए दे दी है। अमरीकी कांग्रेस के समक्ष जब तक यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से मंजूरी के लिए पेश नहीं कर दिया जाता तब तक विभिन्न देशों को बेची जाने वाली सामग्री की निश्चित सूची मालूम नहीं हो सकेगी; बहरहाल, जहां-तक हमें मालूम है यह बिक्री पिछले कई वर्षों से चल रहे एक कार्यक्रम का अंग है जिसका संबंध अमरीका द्वारा पाकिस्तान को विगत वर्षों में दिए गए उपकरणों के पुनर्नवीकरण से है।

जैसाकि सदन को मालूम है भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाया है और हमारी यह चेष्टा है कि इस क्षेत्र के देशों के साथ अधिकाधिक लाभदायक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाए ताकि हमारा उपमहाद्वीप तनावमुक्त तथा सुदृढ़ता का क्षेत्र बने। हमारा विश्वास है कि हमारा यह प्रयास एशिया की शांति के व्यापक हित में है और इसका स्वागत उन

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

तमाम शक्तियों द्वारा रचनात्मक प्रोत्साहन देने और संयम दिखा कर किया जाना चाहिए, जिन्होंने इन प्रवृत्तियों पर संतोष व्यक्त किया है ।

हम लोगों ने पहले भी कई बार और अभी हाल ही में अपनी चिंता अमरीकी सरकार के ध्यान में ला दी है कि हथियारों की बिक्री से खतरा पैदा हो सकता है और आज जो प्रक्रिया चल रही है उसमें रुकावट भी पैदा हो सकती है। भारत सरकार ने इस समाचार पर संतोष व्यक्त किया है कि राष्ट्रपति कार्टर ने विकासशील देशों में हथियारों की बिक्री और हस्तांतरण के संबंध में संयम बरतने के पक्ष में अपने विचार प्रकट किए हैं। अभी बिल्कुल हाल ही, विगत 17 मार्च को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के विशेष अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कार्टर ने कहा संसार के उन हिस्सों में जहां खतरे मौजूद हैं वहां शस्त्रों के प्रवाह को कम करने की दिशा में विशेष प्रयास अवश्य किए जायें। तदनुसार हम लोग उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्रों के बीच व्यापक समझौते का प्रयास करेंगे जिससे पारस्परिक शस्त्रों के निर्यात पर रोक लगे और हम अपनी ओर से भी इस दिशा में पहल करेंगे, चूंकि संयुक्त राज्य अमरीका स्वयं संसार के प्रमुख शस्त्र विक्रेताओं में से एक है। अतः हमारी यह आशा है कि अमरीका की शस्त्र विक्रय नीति संबंधों के सामान्य बनने की प्रक्रिया में न तो बाधक बनेगी और न ही तनावों को फिर से उत्पन्न होने देगी, चूंकि यदि ऐसा हुआ तो इस उपमहाद्वीप में एक शस्त्र दौड़ प्रारम्भ होने की आशंका है और यदि ऐसा हुआ तो इस क्षेत्र के निवासियों पर अधिकाधिक आर्थिक दबाव आ पड़ेगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपसभापति जी, भारतीय विदेश विभाग और विदेशी मंत्री के पद की अभी तक यह परम्परा रही है कि उस को दलीय स्तर से प्रायः ऊपर माना जाता है। इसी पृष्ठ भूमि में वर्तमान विदेशी मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अभी जो अपना एक वक्तव्य दिया कि विदेश मंत्रालय पूर्ववर्ती सरकार की किन्हीं नीतियों में परिवर्तन करने नहीं जा रहा है। इसके लिये और इस पद पर आसीन होने के लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही इस ध्यान कर्षण प्रस्ताव के संबंध में 2–3 आवश्यक बातें भी निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि पिछले 10–12 वर्षों से भारत और अमेरिका के संबंध कुछ मधुर नहीं चल रहे हैं। इसका जहां यह कारण रहा है कि भारत की आंतरिक नीतियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का हस्तक्षेप रहा है वहां यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में तनाव पैदा करने के लिये समय-समय पर अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देता रहा है। 1965 से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 मिलियन डालर के हथियार और लड़ाकू जहाज भेजे। इस प्रकार की उनके अपने अधिकृत सूत्र से जानकारी है। लगभग इतने ही मूल्य के हथियार और हवाई जहाज ईरान और साउदी अरेबिया और इनके माध्यम से पाकिस्तान को अमेरिका ने दिये। इस बात को भी भारत लगभग भूल चुका था। पर 1971 के बंगलादेश के मुक्ति संघर्ष में अमेरिका का सातवां बेड़ा जिस निर्लज्जता के साथ बंगाल की खाड़ी में आया, अभी वह पहुंच ही नहीं पाया था कि इतने में बंगला देश का मुक्ति संघर्ष समाप्त हो गया था और ढाका में स्वतंत्र बंगला देश का झंडा लहरा दिया गया, उस समय वह अपना सा मुंह लेकर लौट गया। इससे भी भारत के अंदर रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इसके लिये विशेष रूप से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति निक्सन और पहले विदेश मंत्री किसिंजर, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय दोनों मंचों पर भारत को बदनाम करने की कोशिश की उनके प्रयत्नों से इन संबंधों में खटास पैदा हो गई और विशेष रूप से तब जब हिन्द महासागर में अमेरिका

ने अपना सैनिक अड्डा बनाया और भारत के और दूसरे देशों के विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने किसी प्रकार का परिवर्तन करने की चेष्टा नहीं की । मैं उन सारी बातों के इतिहास में न जाते हुए वर्तमान पर आना चाहता हूं ।

अभी अमेरिका के नये राष्ट्रपति श्री कार्टर के वक्तव्यों से, समय-समय पर जो उन्होंने दिये है, लगता है कि वह अपनी विदेश नीति और भारत अमेरिका के संबंधों में कुछ नया मोड़ लाना चाहते है । नये प्रधान मंत्री के नाम जो उन्होंने एक संदेश भेजा है उससे भी लगता है कि वह भारत-अमेरिका संबंधों में किसी प्रकार से सुधार लाना चाहते हैं । हिन्द महासागर से अपना सैनिक अड्डा हटाने की बात भी उन्होंने अपने वक्तव्यों में कही है लेकिन अकस्मात जो यह धमाका वाशिगटन पोस्ट ने किया इसके लिये वर्तमान विदेश मंत्री ने बताया है कि अभी अधिकृत सूत्रों से इसकी पुष्टि नहीं हुई है । मैं नहीं समझता वाशिगटन पोस्ट जैसा जिम्मेदार अखबार इस बात को किस तरह से प्रकाशित कर सकता है । मै यह जानना चाहता हूं विदेश मंत्रीजी से कि क्या आपने वाशिगटन स्थित अपने राजदूतावास से भी किसी प्रकार की जानकारी ली है ? या फिर वाशिगटन पोस्ट ही इतनी जिम्मेदारी की खबर दे सकता है । जिम्मेदारी की खबर जिसमें छपी है उसमें केवल हथियार देना ही नहीं है बल्कि उसमें लिखा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से एफ-110 जैट लड़ाकू विमान भी मांगें हैं । और यह 20 अरब डालर की डील हो रही है, इसके अन्दर वे विमान सम्मिलित हैं जिनसे पाकिस्तान कहीं भी बैठ कर भारत के किसी भी नगर पर आक्रमण कर सकता है । इतने भयंकर विमान अमरीका से पाकिस्तान ले रहा है तो भारतीय राजदूतावास जो वाशिगटन में है और जो इतना बड़ा राजदूतावास है, अगर वह वहां बैठ कर वाशिगटन पोस्ट में जो समाचार निकला और तब राजदूतावास क्रियाशील हुआ, यानी हमारे राजदूतावास ने किसी भी प्रकार की जानकारी आपको दी या नहीं, पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं ।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने या विदेश मंत्रालय ने अमरीका के विदेश विभाग को या विदेश मंत्रालय को यह बता दिया है या नही कि भारत सरकार शक्ति और सम्पत्ति की भाषा के आगे झुकने वाली नहीं है । जो उसकी प्रारम्भ से ही नीति रही है इसको भारत अपने स्वाभिमान और सम्मान के अनुकूल मानता है और इसे जारी रखना चाहता है और अमरीका इन प्रयत्नों को छोड़े कि वह शक्ति और सम्पत्ति की ताकत के दबाव में आकर भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर सकता ।

तीसरी बात यह है कि अभी पीछे पाकिस्तान के चुनावों में जो स्थिति हुई है और जो आंतरिक संघर्ष पाकिस्तान में चल रहा है, मेरी अपनी ऐसी जानकारी है कि पाकिस्तान के नये प्रधान मंत्री उसको नया मोड़ देने के लिए भी कुछ छेड़-छाड़ की गतिविधियां शायद निकट भविष्य में करने की सोच रहे है । ऐसे समय में वाशिंगटन पोस्ट में इस समाचार का निकलना या अमरीका के अंदर इस प्रकार की चर्चा का आना चिंतनीय है । वहां कांग्रेस का सबसे बड़ा संगठन है उस संगठन के सामने बात जाएगी और इसलिए जाएगी कि ढाई करोड़ डालर से ज्यादा के हथियार किसी को भेजने हों तो वह बात कांग्रेस के सामने जाती है और यह तो 20 अरब डालर के हथियार हैं । तो मै जानना चाहता हूं कि भारतीय राजदूतावास ने क्या उनके विदेश मंत्रालय को भारतीय नीति की जानकारी दे दी है या नहीं और अगर भारतीय राजदूतावास ने यह जानकारी नही दी है तो क्या हमारे विदेश मंत्री संसद के माध्यम से देश को और अमरीका विदेश विभाग को यह आश्वासन देंगे कि अगर उन्होंने कोई इस प्रकार की कार्यवाही की तो

[प्रकाशवीर शास्त्री]

अमरीका जो नया मैत्रीपूर्ण हाथ भारत की ओर बढ़ाना चाहता है, इस प्रकार की कार्यवाही को अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही समझा जाएगा। आप इस प्रकार का आश्वासन दें ताकि हमको यह पता लगाना चाहिए कि भारतीय उप-महाद्वीप में फिर से तनाव की स्थिति अमरीका जैसे अब तक पैदा करता रहा है, भविष्य में किसी प्रकार पैदा न करे या फिर यह कि अमरीका के जो नये विदेश मंत्री हैं उनसे नये हमारे विदेश मंत्री की किसी प्रकार की कोई मुलाकात हो और उसमें इस प्रकार की बात रखी जाए। मैं इन सब बातों के बारे में जानना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय या विदेश विभाग की क्या नीति है और भविष्य के लिए वह क्या सोच रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य की इन भावनाओं से सहमत हूं कि विदेश नीति हमारे यहां राष्ट्रीय मतैक्य के आधार पर निश्चित होती रही है, चलती रही है। भविष्य में भी ऐसा हो हो, यह हमारा प्रयत्न रहेगा।

जहां तक पाकिस्तान को हथियार देने का सवाल है, मैंने अपने वक्तव्य में सरकार की चिन्ता को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। हम तो आशा करते थे कि अभी तक जो कुछ हुआ उसको पीछे छोड़ कर मैत्री को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न प्रारम्भ किया जाएगा। लेकिन यह तो 'प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः' वाली कहावत चरितार्थ हो गई। भारत आशा करता था कि किसी भी महा-शक्ति द्वारा और इस समय प्रश्न अमरीका का है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे स्थिति और सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में रुकावट पैदा हो और पाकिस्तान और भारत शस्त्रों की होड़ में पड़े। हथियारों के अम्बार लगाने के बजाय हमें अपने सीमित साधनों का जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारने में उपयोग करना है। शास्त्री जी ने राष्ट्रपति कार्टर के वक्तव्यों का उल्लेख किया है। हम आशा करते हैं कि अमेरिका की कथनी और करनी में मेल होगा और शस्त्रों के बजाय वह मित्रता के आधार पर इस भूखण्ड में स्थायित्व लाने के हमारे प्रयत्नों में योग देगा।

श्रीमन्, भारतीय राजदूतावास के साथ इस संबंध में हम निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं। भारत की तरह से अमेरिका के समाचार-पत्र भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार रखते है। एक तरह से शास्त्री जी को वाशिंगटन पोस्ट को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने यह समाचार छाप दिया तो यह मामला उठाने का अवसर उनको मिल गया। लेकिन समाचार छपने से पहले कुछ तथ्य हमारे ध्यान में लाये गये थे और हम उनके आधार पर अमेरिका सरकार को अपने विचार बताते रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार पाकिस्तान जो हथियार मांग रहा है उनमें टारपी-डोज हैं और एन्टी टेन्क मिजाइल्स शामिल हैं और अन्य शस्त्र भी वह मांग रहा है। इनके साथ और भी साज-सामग्री चाहता है। लेकिन अमेरिका ने क्या निर्णय किया है, इसके बारे मे हमें जानकारी नहीं है। जब जानकारी उपलब्ध होगी तो मैं सदन को विश्वास में लेने का पूरा प्रयत्न करूंगा।

SHRI KALYAN ROY (West Bengal): Sir, I must confess that I am rather disappointed with the statement of the Minister of External Affairs. I thought that there would be indignation. but instead of indignation, I find that he has been submissive in his approach to this massive arms sale to Pakistan. My first question to the Minister of External Affairs is this. Is it not a fact that today the U.S.A. is the biggest pedlar of arms in the world? The *military industrial complex or* dependence of one on the other in regard to arms is bound to lead to this kind of development. Frstly, the survival of the monopoly capital regime there with bases from Diego

Garcia to Congo depends on the export of arms. Secondly, the arms export and sale as a part of the American foreign policy is meant to destabilise the situation in the Middle-East, in South-East Asia, in Africa and in Latin America. Thirdly, this is meant to create spheres of influence and to endanger the freedom of the non-aligned countries. Mr. Vajpayee is aware how America and the U.S. Government went out of their way to topple the Government of Dr. Allende in Chile. He is aware of the supply of arms to the colonial regimes in Africa. He is also aware that today, they are sending massive arms to South Africa and Rhodesia. The entire U.S. foreign policy is based on one thing, to topple the non-aligned governments in order to replace them by stooges of the American imperialistic policy. I am surprised that today even Mr. Vajpayee is relying on the Washington Post instead of asking his ambassador there to give him the latest information. Mr. Vajpayee, is it not a fact that after the lifting of the arms embargo last year, the first sale was to the tune of 70 million dollars which consisted of T.O.W. anti-tank missiles which were sent to Pakistan? This is the second arms deal which is worth 83 million dollar. This is out of the arms worth two billion dollars which is supposed to be in the pipeline to other countries. Another three billion dollars worth of arms are going to be supplied to Pakistan, Indonesia, Rhodesia, South Africa and Iran. Is it so innocent? Is it not true the word 'sale' itself is a misnomer? Actually this is a gift. There will be no purchase and the massive supply is going to increase further. Will Mr. Vajpayee agree that this kind of massive arms sale to Pakistan which during the last 10 years amounted to Rs. 8 to 10 million dollars is the single biggest factor responsible for the tension in the sub-continent, leading to arms race and threat to peace, sovereignty and integrity of India, and not only to India but to the non-aligned countries and Arab countries which are trying to shake off the shackles of American Government and its stooges? Is it also not a fact—it came in the American press—that it is not only the American Government but the various multinational manufacturing companies which are manufacturing arms are also sending massive arms supplies to Pakistan The Varadyne Industries Inc. was indicated by the Grand Jury of the United States for supplying anti-radar device, called "Ralar" for use by the Pakistani Air Force. All these things are there. Only addition has been done by Mr. Moynihan who said.

All that India can export is communicable diseases. We have got our Ambassador there and the United States Government has got their Ambassador here—First Secretary or whoever he may be. Has Mr. Vajpayee called the Ambassador, has any note of protest been submitted to the United States Government? Has it been taken up with the United States Government whether the re-

[Shri Kalyan Roy]

port is true, and if it is true, we may severe diplomatic relations because it is no use maintaining relations in this state of affairs. The American supply of arms to Pakistan; we know it will be not only used against India but it will be used against those parts—Baluchistan, North East Frontier etc.—also. It is also not liked by the opposition democratic forces in Pakistan. These arms may be used to suppress the democratic forces inside Pakistan. These developments are already taking place.

I would, therefore, humbly ask Mr. Vajpayee to be a little more indignant and call the American Ambassador to his office and ask him and take him to task as to why this is happening or ask the Ambassador openly and publicly to protest to the new American President, Mr. Carter, that this type of deal which is going on is likely to impede the relations between the United States and India.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किए हैं। वह विचार जाने माने विचार है । उनकी सभी बातो से मेरे लिए सहमत होना सम्भव नही है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर बहस हो तो विस्तार से सभी प्रश्नों की चर्चा हो सकती है। यह धारणा ठीक नही है कि हमने अमरीका की सरकार से इस बारे में सम्बन्ध स्थापित नहीं किया। वाशिंगटन स्थित हमारा राजदूतावास अमरीका के साथ निरन्तर सम्पर्क में है। यहां भी विदेश मंत्रालय उनके दूतावास से बातचीत करता रहा है। हमने अपनी चिन्ता असंदिग्ध शब्दों में प्रकट की है।

श्री हर्षदेव मालवीय (उत्तर प्रदेश) : आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, इनका यह प्रश्न है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपसभापति महोदय, मैं जहां शास्त्रों को बेचकर मुनाफा कमाने की बात है, हम तो सभी देशों से यह कहना चाहते है कि वे मौत का सौदागर बनने का प्रयत्न न करें। लेकिन दुनिया में शस्त्र बेचने की भी एक होड़ लगी हुई है। हम आशा करते हैं कि ये होड़ रूकेगी।

जहां तक भारत की सुरक्षा का प्रश्न है मैं यह सदन को आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि इस भूखण्ड में जो भी नए परिवर्तन हो रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी सुरक्षा के प्रयत्नों को और भी मजबूत करेंगे और भारत की सीमाओं को किसी भी तरह संकटापन्न नहीं होने देगें।

SHRI KALYAN ROY: Sir has he replied to any one of my question?

I asked specific questions whether the American Ambassador was called to the External Affairs Ministry and told that the Indian Government protests against this kind of arms deal, whether our Ambassador there has met the External Affairs Secretary there, protesting against this and whether in view of the massive arms deal, the Indian Government have taken it up most seriously with the American President that this sort of arms deal is going to lead to serious deterioration of relations between the two States.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपसभापति महोदय, मैंने इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

SHRI KALYAN ROY: Was the American Ambassador called?

SHRI M. R. KRISHNA (Andhra Pradesh): He has answered as Defence Minister, not as Minister for External Affairs.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I think my friend is asking the question as a former Minister connected with Defence.

SHRI M. R. KRISHNA: You have answered as though you are Defence Minister. We would like you to answer as the Foreign Minister.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, I don't know if there could be watertight compartments so far as questions of Foreign Affairs and Defence are concerned.

श्री कल्याण राय : वाजपेयी जी हमारे सवाल का जवाब दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपसभापति महोदय, अमरीकी राजदूत इस समय दिल्ली में नहीं है इसलिए उनको बुलाने का सवाल पैदा नहीं होता। जो है उन को बुला कर बात की गई है, मैं यह पहले कह चुका हूं।

श्री रबी राय (उड़ीसा) : उन्होंने सुना नहीं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (राजस्थान) : कड़ा विरोधपत्र क्यों नही भेजा गया, कड़ा विरोध क्यों नही किया गया ? इस पर हमारी मिनिस्ट्री चुप क्यों रही ?

श्री रबी राय : उपसभापति महोदय, यह खुशी की बात है कि हमारे नए विदेश मंत्री इस सिलसिले में चिंतित है कि पाकिस्तान को युनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका से अस्त्र बेचने के सिलसिले में वाशिंगटन पोस्ट में संवाद निकला है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या उनका ध्यान उस खबर की तरफ गया है, जैसा कि सवाल कल्याण राय जी ने उठाए थे कि चिली में जिस तरह से सी० आई० ए० के जरिए हस्तक्षेप हुआ था, उसी तरह कार्टर साहब राष्ट्रपति बनने के बाद उनके भूतपूर्व राष्ट्रपति के जमाने में जो हस्तक्षेप हुआ था, उसके लिए कार्टर साहब ने चिली की जनता से, जनसाधारण से क्षमा मांगी है। तो जब इस समाचार की ओर वाजपेयी साहब का ध्यान गया है, मैं उनसे जानना चाहता हू कि वह जो परिवर्तित परिस्थिति है उसमें अमरीका का जो जनमत है, जैसे कि सीनेटर हम्फ्री हैं, सीनेटर कैनेडी हैं, इस तरह की उदारवादी परम्परा के सीनेटर हैं और वहा का जो बुद्धिजीवी है उनके साथ संपर्क का रास्ता बना है, तो वहां के जनमत को प्रभावित करने के लिए कि इस तरह का सौदा न हो इस सिलसिले में हमारी सरकार ने क्या पग उठाया ?

दूसरा सवाल है : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से अतीत से अतीत में अमरीका के अस्त्र टर्की और ईरान के जरिए पाकिस्तान को आते थे, मैं मंत्री महोदय से

[श्री रबी राय]
जानना चाहता हूं, इस तरह से जो पहले हुआ करता था, अभी वह स्थिति है कि नहीं है? इतने ही दो सवालों का जवाब चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपसभापति महोदय, मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहूंगा। पाकिस्तान अन्य सूत्रों से भी शस्त्र प्राप्त कर सकता है, करता रहा है। यह बात भी हमने अमरीका के ध्यान में लाई है। जहां तक आंतरिक मामलों में हस्तक्षप का प्रश्न है, हम चौकन्ने हैं और किसी भी शक्ति को अपने घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं देंगे।

श्री हर्षदेव मालवीय : मान्यवर, हमारे विदेश मंत्री जी ने कार्टर महोदय का एक बयान उद्धृत किया। कुछ बड़ी आशाएं उनको मालूम पड़ती हैं कि अमरीका बुद्धि की बात समझेगा और उन्होंने इसीलिए अब तक प्रोटस्ट नहीं किया। हमको इस बात पर आश्चर्य नहीं है, चूंकि, अगर मैं गलत नहीं कहता, सन् 1964 या 1965 में माननीय विदेश मंत्री महोदय अमरीका गए थे और श्री गुरु गोलवलकर का एक संदेश ले कर गए थे, जिस संदेश में गुरु गोलवलकर ने कहा था कि अमरीका धर्म-युद्ध लड़ रहा है वियटनाम में और हम अमरीका के साथ हैं। खैर, पुरानी बात हैं। भुलाइए।

मैं कहना चाहता हूं कि अमरीकी राष्ट्रपति के बयान पर भरोसा करना बहुत गलत है; हमारे पास काफी अनुभव है इसका। प्रसीडेंट कैनेडी आए, दुनिया ने उनको पूजा, फिर उन्होंने "बे आफ पिग्ज" कराए। वियटनाम में उन्होंने कत्ल कराया। कार्टर साहब जब चुनाव लड़ रहे थे तो कहते थे कि हम डिक्टेटरशाही का समर्थन नहीं करेंगे और फिर भी पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं। पाकिस्तान को जनतंत्र कहना अपने को भुलावे में डालना है। अमरीकी नीति इस महाद्वीप में, जैसा हमारे माननीय शास्त्री जी ने कहा, बराबर टेंशन बनाये रखने की है, झगड़ा फसाद बनाये रखने की है। भारत मजबूत न हो, भारत कमजोर रहे यह उनकी सतत नीति है। अमरीका पाकिस्तान को जो वर्तमान में हथियार देने जा रहा है उसको इस पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। बात क्या है? बात यह है कि वहां पर शासन पर और शासनकर्ताओं पर एक मिलिटरी इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स का प्रभाव है। वह सी० आई० ए० कन्ट्रोल करता है, वह पेन्टागन कन्ट्रोल करता है। ये एतिहासिक बातें हैं। आज की बातें आप जानते हैं। वह चाहते हैं कि हथियार बेचा जाय। लड़ाई होगी तो उनका हथियार व्यापार चलेगा। दो बिलियन डालर का हथियार वह बेच रहे हैं। यह कहा गया है कि जहां पर किसी देश का ढाई करोड़ डालर से अधिक के हथियार दिये जायेंगे तो वह मामला यू० एस० कांग्रेस के सामने पेश होगा, क्या माननीय मंत्री महोदय को विदित है कि कितने मूल्य के हथियार पाकिस्तान को दिये जा रहे हैं? आपने दो-एक चीजें बतायीं कि टारपीडो वगैरह बेचे जा रहे हैं। वहां के वाशिंगटन पोस्ट की खबर में बताया गया है जो हथियार बेचे जा रहे हैं वे रिलेटिवली नान-कन्ट्रोवर्शियल हैं। मगर नान-कन्ट्रोवर्शियल हथियार क्या होते हैं, क्या हथियार ऐसा होता है जो हत्या नहीं करता? जो हत्या करता है उसको नान-कन्ट्रोवर्शियल कहने का क्या अर्थ है?

एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान ने 110 एस-7 जेट अटैकर वायुयान मांगे और उसके लिए डालर में पेमेंट करने को तैयार है। यह वायुयान ऐसा भयंकर है कि भारत के किसी भी भाग पर वह आक्रमण कर सकता है। यह बड़ी खतरनाक बात है। तो हम चिन्तित हैं। मैं माननीय मंत्री जी की और उस पक्ष के साथियों की देशभक्ति में, भारत के प्रति प्रेम में, कोई सन्देह नही रखता। इस स्थिति से हम चिन्तित हैं; वे भी चिन्तित हैं।

मैंने पहला सवाल किया कि कौन से हथियार खरीद रहे हैं इसका विवरण हम चाहते हैं। क्या उनमें एस-7जैट अटैकर भी हैं ? अभी तक प्रोटस्ट क्यों नहीं किया गया ? इसके साथ ही मेरा सवाल यह है कि इस खतरे का मुकाबला करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ? हमारे पास अभी तक जो हथियार आते रहे हैं वे सोवियत देश से आते रहे। सोवियत देश गाढ़े वक्त हमारे काम आया, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है हमारे आदरणीय माननीय प्रधान मंत्री, जिनका हम सब आदर करते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, कभी-कभी कुछ बचकानी बात कह जाते हैं जैसे आज उनको क्षमा मांगनी पड़ी महिलाओं के सम्बध में कह कर। उन्होंने यहां तक इशारे से कह दिया कि हम इन्डो-सोवियत ट्रीटी को कम करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, एब्रोगेट करेंगे। क्या वे यह भूल जाते हैं कि हमारे देश के काम सोवियत देश ही आया ? क्या वे इस सम्बन्ध को बिगाड़ना चाहते हैं ? क्या इस भयंकर अस्त्र का मुकाबला करने के लिए उन्होंने कोई हथियार सोवियत देश से लेने की बात सोची है ? अमरीका की नीति है "आग लगाय जमालो दूर खड़ी", पाकिस्तान को भी हथियार दे दो, भारत को भी हथियार दे दो, दोनों लड़ें और नुकसान हो और वे हथियार बेचते रहें। उधर से तो इशारा है कि अगर भारत हथियार चाहेगा तो भारत को भी हम देंगे। क्या ऐसा तो आपका कोई विचार नहीं है कि आप भी वहां से हथियार मांगें ? क्या भारत सरकार यह आश्वासन देगी कि वह अमरीकी साम्राज्यवाद की इस शैतानी चाल में नहीं पड़ेगी ? एक अंतिम बात। हमारे माननीय मंत्री जी ने जब से उन्होंने विदेश मंत्री का पद सम्हाला है--पिछली बातें तो मैं भुला देता हूं, कहना नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद जो उन के वक्तव्य आये हैं वह स्वागत योग्य वक्तव्य हैं। रामलीला ग्राउण्ड में जो भाषण उनका हुआ उसमें इजराइल और अरब के संबंध में उन्होंने बड़ी शानदार बात कही। अपने यहां संवाददाताओं का जो एक रिसेप्शन किया, अपने घर पर, वहां जो आप का वक्तव्य निकला वह बहुत अच्छा था। मेरे पास कटिंग है, लेकिन उसे पढ़ कर मैं आपका समय नहीं लूंगा। उसमें आपने स्पष्टतः कहा कि हम पाकिस्तान से उत्तरोत्तर दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं इसका। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, देश चाहता है। वह हमारे भाई हैं, पड़ोसी हैं। तो क्या इस संबंध में आप इस प्रकार से विचार करेंगे कि पाकिस्तान के सम्मुख आप एक प्रस्ताव रखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नान-एग्रेशन पैक्ट पर दस्तखत हो जायं ? क्या इस संबंध में आप पहल करने को तैयार हैं ? क्या विचार है आपका ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपसभापति महोदय माननीय सदस्य ने पुराने मामलों को न उठाने की बात कहते हुए भी एक पुराना मामला उठा दिया।

श्री हर्षदेव मालवीय : वह बात सही है। आप ऐसा संदेश ले गये थे, यह सही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपसभापति जी, मैं अमरीका गया था, स्वर्गीय गोलवलकर जी का संदेश मैं अमरीका की सरकार के नाम नहीं ले गया था। अमरीका में बसे हुए भारतीयों के नाम ले गया था।

श्री हर्षदेव मालवीय : बहरहाल, वियतनाम की हत्या हो रही थी। उसकी आपने धर्मयुद्ध कहा था। वियतनाम की जनता मारी जा रही थी और आपने उसे धर्मयुद्ध कहा था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपसभापति महोदय, मैं इन विचारों का खंडन करना चाहता हूं कि मैंने उसको धर्मयुद्ध कहा। मैंने कभी उसको धर्मयुद्ध नहीं कहा और मेरी माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि सदन में ऐसी बातें करने से पहले वह उनके बारे में पक्की जानकारी प्राप्त कर लिया करें तो विदेश नीति के

संचालन की दृष्टि से यह अच्छा होगा। अब मैं उनके प्रश्नों पर आना चाहता हूं।

उन्होंने विदेश मंत्री के नाते मेरे द्वारा दिए गए कुछ वक्तव्यों का स्वागत किया है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं जो कुछ मैंने प्रारम्भ में कहा उस को यदि वह अच्छा समझते हैं तो इस दिशा में मैं आगे भी अच्छी तरह से बढ़ूंगा ऐसा उनको समझना चाहिए, लेकिन शायद इतना समय वह मुझको देना नहीं चाहते।

श्री हर्षदेव मालवीय : पांच साल तो आपके पास है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उप सभापति महोदय, मैंने कुछ हथियारों का संकेत किया था जो कि पाकिस्तान चाहता है। यह सही है कि पाकिस्तान ऐंटी टैंक मिसाइल चाहता है, टी ओ डब्लू, और पाकिस्तान ए-7 एयरक्रैफ्ट भी चाहता है। उस की मांग 110 हवाई जहाजों की है। लेकिन हमारी जानकारी यह है कि अमरीका ने इस मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या भारत अमरीका से हथियार खरीदेगा। श्रीमन् अमरीका से हथियार खरीदने का कोई प्रस्ताव इस समय हमारे सामने नहीं है। जहां तक विरोध पत्र भेजने का सवाल है, क्या इस सदन में, खड़े हो कर अपनी चिन्ता प्रकट करना, भारत जैसे महान देश के लिए इस स्थिति में, आज की स्थिति में पर्याप्त नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार आगे भी जाकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगी

श्री हर्षदेव मालवीय : पाकिस्तान नान-एग्रेशन पैक्ट की बात के बारे में?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय अपने अभिभाषण में कह चुके हैं कि जो सधियां हुई है हम उन का स्वागत करेंगे उनका समर्थन करेंगे। जो समझौता वार्ताएं चल रही है उनको हम आगे बढ़ायेंगे। भारत बहुत पहले से पाकिस्तान को यह आश्वासन देता रहा है कि हमारी कोई विस्तारवादी आकांक्षाएं नहीं है। हम तो सह अस्तित्व के आधार पर इस भू-खण्ड में जीवित रहना चाहते है।

सचमुच में हम यह समझने में असमर्थ कि पाकिस्तान को नए हथियारों की आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए। बंगला देश के निर्माण के बाद उनका रक्ष का दायित्व कम हो गया। हम तो तैयार है युद्ध वर्जन सन्धि के लिए और मैं इस प्रस्ताव को दोहराता हूं, अगर पाकिस्तान इसे स्वीकार करेगा तो बड़ी प्रसन्नता होगी और इस भूखण्ड में फिर स्थायी शान्ति का आधार होगा।

REFERENCE TO THE CLOSURE OF TEXTILE MILLS IN TAMIL NADU

SHRI V. V. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): Sir, in Tamil Nadu most of the textile spinning mills have been virtually closed down due to shortage of cotton and very high price of cotton, Tamil Nadu spinning mills have to import cotton from other States like Maharashtra, West Bengal and U. P. and have to sell the yarn at very low prices to those States. The Government must take serious steps because almost all the spinning mills even efficient mills have been closed down and thousands of workers have been rendered jobless. The recommendations of the Subarna Committee which has given some concrete suggestions, should be accepted by the Government and steps should be taken to supply cotton either by importing from foreign countries or